

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 04 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-277 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

आज भारत आएंगे पुतिन, कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत आने वाले हैं। वहीं, 5 दिसंबर को पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पुतिन का यह दौरा लगातार सुर्खियों में है। पुतिन के आने से पहले भारत और रूस के बीच कई डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें रक्षा समझौता भी शामिल है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पैसेवोव के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनेल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यही वजह है कि रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देगा। नई दिल्ली और मॉस्को के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को भी रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है।

भावनगर की पैथोलॉजी लैब में भीषण आग, राहत-बचाव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर उठा सवाल

- खिड़की तोड़कर नवजातों को चादर में लपेटकर बाहर निकाला

भावनगर (एजेंसी)। गुजरात के भावनगर शहर के काला नाका क्षेत्र में स्थित एक पैथोलॉजी लैब में बुधवार को लगी भीषण आग ने प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हादसे में कई मरीजों तथा कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालना पड़ा। खिड़की तोड़कर नवजातों को चादर में लपेटकर बाहर निकाला गया। हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फायर ऑफिसर प्रद्युमनसिंह जाडेजा के अनुसार, आग पैथोलॉजी लैब के बेसमेंट में लगी और धीरे-धीरे पूरी इमारत में फैल गई। दमकलकर्मियों ने अब तक 15-20 लोगों को स्ट्रेचर और सीढ़ियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक दमकलकर्मियों और 6 फायर ब्रिगेड वाहनों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। आग पर नियंत्रण पाने के बाद कूलिंग का काम जारी है। फिलहाल दमकल टीमें मौके पर हैं और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हादसे ने फिर एक बार मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों और सरकारी निगरानी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

अगर पश्चिमी देश अपनी रैवेये से बाज नहीं आए, तो नुकसान उनका ही होगा - एस. जयशंकर

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजनयिकों ने संयुक्त लेख लिखकर भारत की विदेश नीति पर अप्रत्यक्ष सवाल खड़े किए, जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता और कूटनीतिक मर्यादा पर हमला माना। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पश्चिमी देश अपनी रैवेये से बाज नहीं आए, तो नुकसान उनका ही होगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की सबसे दुर्लभ विदेश यात्राओं में से एक है। पिछले तीन वर्षों से अमेरिका

और यूरोप पुतिन को वैश्विक मंच से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जब पुतिन का 'रेड कार्पेट' वेलकम करता है, तो पश्चिमी देशों की यह महिम कमजोर साबित होती दिखती है। यही कारण है कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही यूरोप के तीन बड़े देशों ने अपना 'नाराजगी अभियान' शुरू कर दिया। भारत में तैनात ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरुन, फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ और जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने एक साझा लेख लिखकर पुतिन को यूक्रेन युद्ध का 'विलेन' बताया और कहा कि रूस शांति चाहता ही नहीं। भारत ने इस लेख पर कड़ा आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि यह कूटनीतिक मर्यादा से परे है।

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव: भाजपा ने 7, आप ने 3, कांग्रेस और एआईएफबी ने 1-1 वार्ड जीता

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में से सात पर जीत हासिल की। गत 30 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। मतों की गिनती आज दोपहर तक खत्म हो गई। दूसरे नंबर पर रही आप को तीन सीटें मिलीं, कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक-एक सीट जीती। वार्ड के हिसाब से आप के अनिल मुंडका से 1577 मतों के अंतर से जीते, शालीमार बाग बी से भाजपा उम्मीदवार अनीता जैन ने 10,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की। भाजपा की वीना असीजा अशोक विहार से जीतीं और सुमन कुमार गुप्ता वांदनी चौक से जीतीं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के इमरान खिंदकर पुतिन को यूक्रेन युद्ध का 'विलेन' बताया और कहा कि रूस शांति चाहता ही नहीं। भारत ने इस लेख पर कड़ा आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि यह कूटनीतिक मर्यादा से परे है।



नए आधार एप में घर बैठे एड्रेस-नाम बदल सकेंगे

मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा शुरू, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं

एजेंसी नई दिल्ली। अब आप घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की फ़ैसिलिटी जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिफ़ा आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने की है। इन बदलावों के लिए यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। एप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से सबकुछ चेंज किया जा सकेगा। इस सर्विस

से दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग, सीनियर सिटिजन और माइग्रेट करने वालों को आसानी होगी। UIDAI के मुताबिक एप के जरिए आधार में अपडेट की प्रोसेस काफी सिंपल है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं है। पूरी प्रोसेस कुछ मिनटों में हो जाएगी। सबसे पहले यूजर्स को AAD-HAAR एप डाउनलोड करना होगा। यहां यूजर्स को अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वेरिफिकेशन करना होगा। आगे इस्तेमाल के लिए 6 अंकों का लॉगिन PIN सेट करना होगा। 6 अंकों का PIN डालकर



आधार एप में लॉगिन करें। स्क्रोल करके नीचे जाएं, सर्विसेज में 'माय आधार अपडेट' पर क्लिक करें। सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट का ही ऑप्शन आएगा, क्लिक करें। यहां जरूरी डिटेल पढ़ें, कंटीन्यू पर क्लिक करें। मौजूदा

मोबाइल नंबर डालें, OTP वेरिफाई करें। नया मोबाइल नंबर डालें OTP वेरिफाई करें। फेस ऑथेंटिकेशन होगा, कैमरे में देखकर एक बार आंख बंद करें खोलें। पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, 75 रुपये जमा करने के बाद प्रोसेस पूरी हो जाएगी।

विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बाद सरकार का यू-टर्न, स्मार्टफोन कंपनियों को बड़ी राहत

फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी एप

नई दिल्ली (एजेंसी)। संचार साथी ऐप पर छिड़े विवाद के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने अपना आदेश वापस दे लिया है। दूरसंचार विभाग ने सरकारी संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने का दिया गया अपना आदेश वापस ले लिया है। बता दें कि सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को हर फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने का आदेश दिया था। यह फैसला, यूजर प्राइवसी और संभावित जासूसी से जुड़ी चिंताओं के बाद लिया गया है। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, 'संचार साथी की बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य



ना करने का फैसला लिया है।'

उधर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ एक दिन में अपनी मर्जी से एप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई

है। संचार साथी एप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को

लोकसभा में कहा कि संचार साथी एप से जासूसी करना न तो संभव है, न ही जासूसी होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एप को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों के जवाब पर कहा- फीडबैक के आधार पर मंत्रालय एप इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव करने को तैयार हैं। संचार साथी एप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ, जब दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ-साथ मौजूदा हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए एप इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया था।

जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना को लेकर गंभीर आरोप लगाए और इसे देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के पास जाति जनगणना को लेकर कोई ठोस रूपरेखा, समयबद्ध योजना या जनता और संसद से संवाद करने की कोई योजना नहीं है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए कहा, कि सरकार ने न तो जाति जनगणना की प्रक्रिया का स्पष्ट ब्यौरा दिया और न ही इसके लिए कोई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला



है- न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा, और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं से सीखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई जा रही। यह बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।

दरअसल राहुल गांधी ने अपने लिखित

प्रश्न में पूछा था, कि दशकीय जनगणना की तैयारी के प्रमुख प्रक्रियात्मक कदम क्या हैं, जिसमें प्रश्नों की तैयारी और कार्यक्रम निर्धारण शामिल हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार जनगणना के सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने की कोई योजना बना रही है और अलग-अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षणों के अनुभवों का अध्ययन किया जा रहा है या नहीं।

सरकार का जवाब

सरकार की ओर से अपने लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानाथ राय ने जानकारी दी, कि आगामी जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण

में जनसंख्या की गणना होगी। उन्होंने बताया कि जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्याह्न रखी गई है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों में यह गणना सितंबर 2026 में होगी। इसी के साथ ही नित्यानाथ राय ने कहा, जनगणना का इतिहास 150 वर्षों से अधिक पुराना है। प्रत्येक जनगणना से पहले पिछले अनुभवों और संबंधित हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। आगामी जनगणना भी इसी प्रक्रिया का पालन करेगी। बहरहाल राहुल गांधी के आरोप और सरकार की प्रतिक्रिया के बीच जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की उम्मीद है।

टीएमसी के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, अगले साल चुनाव जीतेंगे: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से राज्य में तुणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने की दिशा में काम करने को कहा। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनके साथ मालदा उतर से लोकसभा सदस्य खगेन मुर्मू भी थे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला किया था। मोदी ने मुर्मू का हालचाल पूछा और राज्य के भाजपा सदस्यों से कहा कि वे राज्य में लोकतंत्र बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का मुकाबला करें। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से लड़ते रहें। हम इस सरकार को हटा देंगे। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि हमें ये चुनाव जीतना है और हम चुनाव जीतेंगे।' दार्जिलिंग के सांसद राजु बिस्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण और अथक प्रयासों की प्रशंसा की तथा जन संपर्क में उनकी भूमिका और जरूरत के समय राज्य के लोगों के साथ खड़े रहने पर प्रकाश डाला। बिस्टा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, फ़उन्हेन हमें नए जोश के साथ सकारात्मक कार्य जारी रखने और राज्य भर में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की दिशा में और कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।' बिहार में भाजपा-जद यु) गठबंधन की भारी जीत के बाद, भाजपा अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तैयारी में जुट गई है।



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय बेचने वाले अतीत का मजाक उड़ाने वाला एक कुत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जनरेटड वीडियो कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। इस वीडियो में पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चाय बेचते हुए दिखाया गया है, जिसे भाजपा ने उनकी गरीब और ओबोसी पृष्ठभूमि पर हमला करार दिया है। पार्टी ने इसे कांग्रेस की पुरानी कुंठ और अभिजात्य मानसिकता का प्रमाण बताया है। यह विवाद 2014 लोकसभा चुनाव की याद ताजा करा रहा है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अग्र्वर ने पीएम मोदी के चाय बेचने वाले अतीत पर टिप्पणी



करते हुए कहा था, अगर नरेंद्र मोदी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चाय बेचने आना चाहें तो आ सकते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी और पार्टी की सोशल मीडिया प्रभारी रागिनी नायक ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से यह वीडियो साझा किया था। वीडियो में पीएम मोदी को चाय की केतली लिए वैश्विक सम्मेलनों में चाय परोसते हुए दर्शाया गया है। भाजपा ने तुरंत इसे पीएम की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का अपमान बताया और ओबोसी समुदाय के खिलाफ कांग्रेस की कथित षण्णा से जोड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक गरीब,

पिछड़े वर्ग से आए व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने लिखा, नामदारों को यह हमज नहीं हो रहा कि कोई कामदार देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए ये लोग बार-बार उनका मजाक उड़ाते हैं। पूनावाला ने याद दिलाया कि कांग्रेस नेताओं ने पहले ही पीएम मोदी पर 150 से अधिक बार व्यक्तिगत हमले किए हैं, यहां तक कि उनकी मां तक को अपशब्द कहे गए थे।

यह विवाद 2014 लोकसभा चुनाव की याद ताजा करा रहा है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अग्र्वर ने पीएम मोदी के चाय बेचने वाले अतीत पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर नरेंद्र मोदी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चाय

आधार कार्ड देश की सबसे बड़ी आइडेंटिटी सर्विस है, जिसमें 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा जुड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर इसका सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी से डड्ड के जरिए बैंक अकाउंट, सरकारी सब्सडी, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन और डिजिटल सर्विसेज जैसे डिजीलॉकर तक एक्सेस मिलता है। अगर नंबर पुराना हो जाए या खो जाए तो कई समस्याएं हो सकती हैं। अभी तक इसे अपडेट करने के लिए एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता था, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लंबी कतारों का झंझट होता है। लेकिन अब UIDAI डिजिटल तरीके से इसे आसान बनाने जा रहा है।

दित्यांगजन दया के नहीं, बराबरी के हकदार - राष्ट्रपति



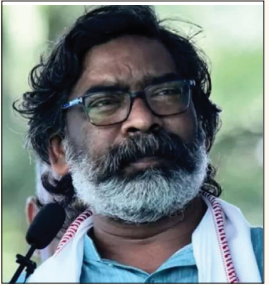
नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में साल 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। ये सम्मान उन लोगों और संस्थाओं को दिए गए जिन्होंने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में बेहतरीन काम किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने साफ कहा, «दिव्यांगजन दया के नहीं, बराबरी के हकदार हैं। समाज और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा, जब हर दिव्यांग व्यक्ति उसमें बराबर का हिस्सेदार बने।। ये कोई एहसान या दान का काम नहीं, बल्कि हम सबका फर्ज है।» इस साल की थीम है - «सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांगता-समावेशी समाज को बढ़ावा देना।» राष्ट्रपति ने कहा कि ये

थीम बिल्कुल सही दिशा दिखाती है। भारत अब पुरानी कल्याण वाली सोच से निकलकर अधिकार और सम्मान वाली सोच अपना रहा है। 2015 में «दिव्यांगजन» शब्द को अपमानकर सरकार ने यही संदेश दिया था कि ये लोग कमजोर नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति वाले हैं।

राष्ट्रपति ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि देश में साइन लैंग्वेज रिसर्च, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए कई राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं। अब तक लाखों दिव्यांगजनों को यूनिफ़ाईडसेबिलिटी आईडी कार्ड मिल चुका है, जिससे उन्हें नौकरी, शिक्षा और यात्रा में आरक्षण व सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं।

झारखंड में भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे हेमंत सोरेन? झामुमो ने सिर से खारिज की साठगांठ की अटकलें

नईदिल्ली,(ईएमएस)। रांची,(ईएमएस)।बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा जेएमएम को एक भी सीट न दिए जाने के बाद से झारखंड की सियासत में अजीबोगरीब अफवाहों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों को उस वक्त और बल मिला जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 28 नवंबर की देर शाम दिल्ली पहुंचे। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल होने लगा कि दोनों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से गुप्त मुलाकात की है और बहुत जल्द झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है। कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन में नाराज चल रहे हेमंत सोरेन एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इन अफवाहों पर तुरंत पूर्ण विराम लगा दिया। पार्टी महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडेय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा पूरी तरह निजी था। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा का काम ही अफवाह और साजिश फैलाना है। लेकिन झामुमो के तीन शब्द हैं- झारखंड झुकेगा नहीं। इन तीन शब्दों से न सिर्फ सारी अफवाहें खत्म हो गईं, बल्कि भाजपा को भी करारा जवाब मिल गया। पांडेय ने कहा कि जनता सब देख रही है और भाजपा को जनानदेश का अपमान बंद कर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए।



कांग्रेस ने दोहराई 2014 वाली गलती: पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाया चायवाला

बेचने आना चाहें तो आ सकते हैं। उस बयान ने कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था और भाजपा ने इसे जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया था। अब एक बार फिर वही मुद्दा एआई के जरिए सामने आया है, जिसे भाजपा फिर से जनता के बीच ले जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले हमेशा उल्टा पड़ते रहे। उनकी मेहनत, संघर्ष और ओबोसी पहचान को लेकर जनता में गहरा लगाव है। ऐसे में यह नया वीडियो कांग्रेस के लिए महंगा साबित हो सकता है, खासकर तब जब भाजपा लगातार पीएम मोदी को 'कामदार बनाम नामदार' की लड़ाई में जनता के बीच ले जा रही है।

पुतिन की भारत यात्रा: नयी विश्व राजनीति की आहट

(लेखक- ललित गर्ग)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा एक साधारण कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इतिहास के सात दशकों में बुनी एवं गढ़ी गई मित्रता का नवीन उद्घोष है। कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं, स्थायी हित होते हैं, किंतु भारत-रूस संबंध इस कथन की परिधि से आगे जाकर स्थायी भरोसे, नैतिक दायित्व और पारस्परिक सम्मान के प्रतीक बने हुए हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका, यूरोप एवं नाटो गढ़बधन रूस पर कठोर आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद भारत ने रूस को न केवल कूटनीतिक स्तर पर सम्मान-साथ दिया बल्कि ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में उसे सबसे भरोसेमंद साझेदार माना। इसलिए यह वार्ता केवल दो नेताओं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात नहीं, बल्कि एक नए युग के सूत्रपात का संकेत है, नयी विश्व राजनीतिक समीकरण की आहट है।

भारत और रूस की मित्रता का इतिहास लगभग 70 वर्षों का है। शीतयुद्ध काल में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर पोखरण परमाणु परीक्षणों तक, रूस ने भारत का साथ दिया। आज जब यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को ध्रुवीकृत कर दिया है, अमेरिका ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बनाया, किंतु भारत ने सामरिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखते हुए रूस का साथ निभाया। पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच भारत ने भारी मात्रा में रूसी पेट्रोलियम और गैस खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की तथा रूस को आर्थिक सहारा दिया। यह निर्णय महज एक वाणिज्यिक लाभ का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय विदेश नीति की स्वयंभूता का प्रदर्शन था। दूसरी ओर, रूस ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। चाहे एस-400 वायु रक्षा प्रणाली हो, टी-90 टैंक हों, ब्रह्मास मिसाइल परियोजना हो या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुयू-57 से जुड़ा सहयोग, भारत की सैन्य क्षमता में रूस का योगदान निर्णायक रहा है। वहीं पाकिस्तान की शत्रुता के खिलाफ भारत के हितों को रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। हाल ही में दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में रूस ने भारत की सामरिक चिंता को समझा और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे

अभियानों में सहयोग की भूमिका निभाई। यह तथ्य भारत-रूस संबंधों की गहराई और विश्वास को दर्शाता है।

पुतिन और मोदी की वार्ता ऐसे समय आयोजित हो रही है, जब वैश्विक शक्ति-संतुलन परिवर्तन के दौर में है। अमेरिका-चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता और पश्चिमी देशों की रूस के विरुद्ध एकजुटता, इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका मध्यस्थ, संतुलक तथा स्वतंत्र धुरी के रूप में उभर रही है। पुतिन भारत को न केवल रक्षा सहयोगी मानते हैं, बल्कि एशियाई भू-राजनीति में संतुलन का स्तंभ भी। वहीं मोदी की विदेश नीति बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें रूस का स्थान केंद्रीय है। इस यात्रा से ऊर्जा सहयोग और बढ़ेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और रूस उसके लिए सस्ता, विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को कच्चे तेल के साथ ही कोयला, गैस और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग दिया। भारत को सस्ती ऊर्जा देने के पीछे केवल व्यावसायिक हित नहीं बल्कि मित्रता और सामरिक साझेदारी भी निहित है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग और विस्तृत होने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा उत्पादन है और रूस इसके लिए सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ है। ब्रह्मास मिसाइल, राइफल निर्माण, स्पेयर पार्ट्स प्लांट और संयुक्त विकास कार्यक्रमों के नए विकल्प वार्ता में उभरेंगे। रूस भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता के रूप में स्थापित करने में सहभागी है, जो संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है।

भारत-रूस दोस्ती अब एक नया अध्याय लिखने को तत्पर है। दोनों देशों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, यहां तक की अमेरिका के साथ बेहतर हुए संबंधों के दौर में भी रूस हमारा विश्वस्त साझेदार बना रहा है, प्रगाढ़ दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती में नई गरमाहट की संभावना के साथ दोस्ती के नये स्वस्तिक उकेरने की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ देश के दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता को संतुलित बनाया है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सलायर है। रूस दोस्ती की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के लोगों को रोजगार देने के लिये भी एक समझौता मसीदा तैयार किया है। रूस अपने उद्योगों के लिए 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों

को काम पर रखना चाहता है।

भारत-रूस संबंधों का सबसे मजबूत आधार है-कूटनीतिक विश्वास और सम्मान। रूस ने कभी भारतीय आंतरिक राजनीति या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कश्मीर, परमाणु नीति, रणनीतिक साझेदारी और पड़ोसी विवादों पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। वहीं भारत ने भी रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझाऊचाहे नाटो विस्तार का मुद्दा हो या यूक्रेन का संघर्ष। इसलिए भारत ने पश्चिमी दबावों की उपेक्षा करते हुए सवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस सहयोगी रहा है और भविष्य की यात्री-वाहक मिशनों में भी सहयोग की संभावनाएँ हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी भी विशेष हैरू योग, आयुर्वेद, साहित्य, रूसी नाट्यकला और भारतीय कलाकृत्यबने एक-दूसरे समाज में स्थान पाया। फिर भी यह संबंध चुनौतियों से खाली नहीं। चीन-रूस साझेदारी और भारत-अमेरिका निकटता के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। रूस चाहता है कि एशिया में भारत संतुलक भूमिका निभाए, वहीं भारत नहीं चाहता कि रूस का झुकाव चीन की ओर अत्यधिक बढ़े। इसी प्रकार रक्षा सहयोग में तकनीक हस्तांतरण, उत्पादन विलंब और आर्थिक भुगतान व्यवस्थाओं पर भी मतभेद रहे हैं। किंतु इन मतभेदों को वार्ता द्वारा समाधान के प्रयास दोनों राष्ट्रों की परिपक्वता को दर्शाते हैं।

पुतिन की इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि यह बताती है कि भारत किसी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संबंध तय करता है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आत्मनिर्भरता, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और एशियाई सामरिक संतुलन की दृष्टि से भारत-रूस साझेदारी अपरिहार्य



है। मोदी और पुतिन की मुलाकात इस विश्वास की प्रमाणिकता है कि संबंध केवल शीत युद्ध की स्मृतियों पर नहीं, बल्कि समकालीन हितों और भविष्य की रणनीति पर आधारित हैं। यह यात्रा एक प्रतीक है-स्वतंत्र विदेश नीति, सामरिक साझेदारी और सांस्कृतिक सम्मान की। भारत-रूस संबंध केवल दो राष्ट्रों की निकटता का परिचय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक विशिष्ट वैकल्पिक शक्ति संरचना का निर्माण है। पश्चिमी देशों की आलोचना और प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस ने अपने संबंधों को न केवल जीवित रखा बल्कि सुदृढ़ किया।

इस मुलाकात से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति मिलेगी, रक्षा उत्पादन को स्वदेशीकरण का बल मिलेगा, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग विस्तृत होगा और रणनीतिक विश्वास की डोर और मजबूत होगी। पुतिन और मोदी की यह वार्ता बताती है कि भूराजनीति केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि भरोसे और सहयोग पर भी टिकती है। अतः कहा जा सकता है कि पुतिन की भारत यात्रा एक नई ऊर्जा, नए दृष्टिकोण और नई साझेदारियों की शुरुआत है-जहाँ भारत और रूस न केवल मित्र हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलित, स्वाधीन और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माता भी हैं। यह यात्रा उसी निर्माण का नवीन अध्याय है, जिसमें पुराने भरोसे से जन्म ले रहा है एक नया भविष्य।

संपादकीय

डिजिटल अरेस्ट

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक टगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकजा करने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर टमों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन-देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार य्म्यार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निरसंदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों-टुकड़ों में जांच सीमा-पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है। दरअसल, साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिये भोले-भाले लोगों व बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। वे कानून प्रवर्तन अधिकारी या जज बनकर मोटी रकम देने के लिये उन्हें आतंकित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति से एक करोड़ रुपये की टगी के बाद अदालत ने इस व्यापक समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। उन्हें धमकाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेशों का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति है कि साइबर अपराधी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल रहे हैं। तभी शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, देश की केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की तह तक तुरंत पहुंचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग को भी सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिये कहा गया है। निश्चित रूप से कोर्ट की सार्थक पहल के बाद यदि ये सभी उपाय सिर्रे चढ़ते हैं तो इस गंभीर अपराध के खिलाफ एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दे पाना संभव होगा। कोर्ट ने विश्वास जताया है कि केंद्रीय एजेंसी बिना किसी भय या पक्षपात के जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

विचार मंथन

लेखक- सनत जैन

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मुद्रा में गिरावट तथा भारत में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मजबूती ने देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से चिंताजनक निकासी के कारण भारतीय रुपया तेजी से गिर रहा है। 3 दिसंबर 2025 को रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर चुका है। इस गिरावट की कई वजह हैं, जिनमें डॉलर की मांग में भारी वृद्धि, भारत में विदेशी पूँजी की आवक में गिरावट, निर्यात-आयात के बीच बढ़ता हुआ असंतुलन प्रमुख हैं। इस वजह से रुपया अब इतिहास की सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है। यह हालत आज अचानक नहीं बनी है। 2013 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वह तत्कालीन मनमोहन सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा करते थे, देखिए रुपया किन्ती तेजी से गिर

रहा है। कभी-कभी लगता है, रुपया और दिल्ली की सरकार में कोई मुकाबला चल रहा है। किसीक ड़्ज़त पहले गिरती है। 2013 में कसा हुआ यह तंज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भारी पड़ रहा है। उस समय मुद्रा गिरावट को गंभीर संकट बताया गया था। 2025 आते-आते वही रुपया आज मनमोहन सिंह के समय से दुगुनी गति से गिर रहा है। जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है। पिछले कई वर्षों से रिजर्व बैंक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की गई। अर्थाशास्त्रियों को वर्तमान सरकार ने अनदेखा किया और मनमाने तरीके से वित्तीय फैसले लिए। रिजर्व बैंक में भी सरकार का दबाव काम करने लगा, जिसके कारण स्थिति दिनों-दिन खराब होती रही है। पिछले एक दशक में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदम वित्तीय स्थिति में सुधार कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं रहे। रुपया गिरने का मतलब है, भारत

में आयात महंगा होगा। आम आदमी पर महंगाई की मार झेलना पड़ेगी। इसका असर आयात और निर्यात पर बड़े पैमाने पर पड़ेगा। भारत में आयात ज्यादा हो रहा है। उसके मुकाबले निर्यात बहुत कम है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में निवेश नहीं किया जा रहा है। प्रवासी भारतीयों द्वारा जो पैसा भारत भेजा जा रहा था उसमें भी भारी कमी देखने को मिल रही है। मुद्रास्फीति पर दबाव बन गया है। विदेशों से भेजे जाने वाले पैसों की कीमत गिर सकती है। निर्यात-आधारित सेक्टरों को अल्प-काल के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में वर्तमान रूपध की गिरावट के कारण आर्थिक अस्थिरता तेजी के साथ बढ़ेगी। सरकार को इस गंभीर स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। सिर्फ बयानबाज़ी और भावना भरोसे बैठकर यह मान कर चलेंगे, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, वर्तमान में यह संभव नहीं है। भारत सरकार के ऊपर कई लगातार बढ़ रहा है। महंगाई बेरोजगारी

और बाजार में मांग कम होने से सगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र में मांग घटती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को ठोस नीतिगत सुधार के कदम तुरंत उठाने चाहिए। रिजर्व बैंक में और सरकार के वित्त मंत्रालय में अच्छे अर्थाशास्त्रियों की सलाह से ऐसे कठोर निर्णय लेने चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए और रुपए की गिरावट को रोकना जा सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में खुलापन लाना पड़ेगा। विदेशी पूँजी भारत में वापस आए इसके लिए निवेशकों के लिए भरोसेमंद माहौल को बनाना होगा। डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करना होगी। अमेरिका की आर्थिक मंदी के बाद जिस तरह की स्थिति 2009 से 2014 के बीच में बनी थी, उससे कहीं ज्यादा खराब स्थिति आज सच होती दिख रही है। रुपया जिस तेजी के साथ गिर रहा है उससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भारत के ऊपर से कम हो रहा है। भारत सरकार द्वारा

पिछले 10 वर्षों में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक पर सरकार का भारी दबाव है। वित्त मंत्रालय भी राजनीतिक आधार पर निर्णय कर रहा है। वास्तविक आर्थिक स्थिति पर उसका कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण स्थिति दिनों-दिन खराब होती चली जा रही है। जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है वह आर्थिक आपातकाल से कम नहीं है। अर्थव्यवस्था को संभालने आयात और निर्यात व्यापार में संतुलन बनाने और घाटे के बजट को संतुलित करने की दिशा में सरकार को गंभीरता के साथ काम करना होगा। अन्यथा जिस तरह की बैंकों की स्थिति है, लगातार एनपीए बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने जिस तरह से गलत निवेश किया है, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था महासंकट की स्थिति में पहुंच गई है।

हर लहर पर तिरंगा : नौसेना का अदम्य जोश और जज़्बा

(लेखक - दिलीप कुमार पाठक /)

04 दिसम्बर भारतीय नौ सेना दिवस)

भारतीय नौसेना का इतिहास 1612 में शुरू हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए समुद्री बल का गठन किया था। समय के साथ यह बल भारतीय नौसेना के रूप में विकसित हुआ। 1950 में रॉयल इंडियन नौसेना का नाम बदलकर भारतीय नौसेना रखा गया। भारतीय नौ सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हुए भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह दिन कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे नौसैनिक योद्धाओं की अदृट भावना और बेमिसाल साहस का प्रतीक है य

भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना की बहादुरी, और समर्पण का सम्मान करता है। यह ऑपरेशन द्राइडेंट की सफलता की स्मृति में मनाया जाता है, जब 4 दिसम्बर 1971 भारत-पाक युद्ध के दौरान नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसेना मुख्यालय को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था, इस अभियान का नेतृत्व कमोडोर के.पी. गोपाल राव ने किया था, जिसमें आईएनएस वीर, आईएनएस निपट और आईएनएस निर्घट जैसे मिसाइल बोट्स का उपयोग कर तीन पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया था य इस हमले में पाकिस्तान के लगभग 300 सैनिक मारे गए और 700 घायल हुए थे य इस ऑपरेशन को ऑपरेशन द्राइडेंट के नाम से जाना जाता है य इस हमले में पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ था, कराची बंदरगाह के ईंधन भंडार को काफी नुकसान हुआ था य कहा जाता है कि इस हमले का आदेश बंद लिफाफे में नौसेना के पास पहुंचा था य भारत ने अपने तीन युद्धपोतों आईएनएस निपत, आईएनएस निरघट और आईएनएस वीर की सहायता से कराची बंदरगाह पर हमला किया, भारत से युद्धपोत गुजरात के ओखा पोर्ट से पाकिस्तान के लिए दोपहर 2 बजे



अनुभव का लाभ

एक विदेशी राजा ने भारत पर आक्रमण करना चाहा। उसने सोचा कि आक्रमण से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि उस राजा के पास कोई बुद्धिमान व्यक्ति है या नहीं? उस राजा ने सुरमे की एक डिब्बिया देकर एक दूत भेजा। उस डिब्बिया में दो आंखों में ही लगाने लायक सुरमा था। वह सुरमा अंधे को आंख देने में समर्थ था। दूत आया। दूत ने कहा, दो आंखों में ही आ जाए, इस डिब्बिया में इतना-सा सुरमा है। हमें इसकी अधिक आवश्यकता है। आपके पास हो तो हमें दें। या इस सुरमे के आधार पर कोई

व्यक्ति हँसा ही सुरमा बना सके तो हम उस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहेंगे।

राजा ने मंत्रियों से सलाह ली। किन्तु हँसा सुरमा कौन बना सके? किसी को समाधान नहीं आया। राजा ने सोचा, एक बूढ़ा मंत्री था, जो अभी सेवानिवृत्त हुआ है, उससे पूछ जाए। राजा ने उसे बुला भेजा। वह अंधा हो गया था। वह आया। मंत्री ने डिब्बिया ली। एक आंख में सुरमा लगाया। कुछ ही क्षणों बाद उसे दिखने लगा। जो शेष सुरमा बचा था, उसे अपनी जीभ पर

रख लिया। स्वाद से उसने सुरमे के सारे द्रव्यों का विश्लेषण कर लिया। घर जाकर वैसा ही सुरमा बनाया। परीक्षण के लिए अपनी दूसरी आंख में उसे लगाया। आंख खुल गई। उसने शेष सुरमा डिब्बिया में भरकर दूत से कहा, जाओ, अपने सम्राट से कहना कि हँसा सुरमा जितना चाहे यहां से मंगा लें। दूत गया। सम्राट को वृत्तान्त सुनाया। सम्राट ने सोचा, जिस देश में हँसे अनुभवी और वृद्ध रहते हैं, इतने बुद्धिमान मंत्री हों, उस देश पर आक्रमण करना भयंकर भूल होगी।



हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, हमारे व्यापार मार्गों की सुरक्षा और हमारे द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना की अदृट प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का दिन है। यह हमारे महासागरों को सुशोभित करने वाले तकनीकी चमत्कारों पर आश्चर्यचकित होने का दिन है - चुपके से चलने वाली पनडुब्बियां, भव्य विमान वाहक, फुर्तीले विध्वंसक और गहरे सागर के मूक रक्षक - ये सभी भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति के प्रमाण हैं। नौसेना दिवस उन पुरुषों और महिलाओं के बारे में भी है जो इन मशीनों के पीछे मजबूती से खड़े हैं। यह उनके अदृट समर्पण, उनके अथक प्रयासों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में उनके अदम्य साहस के बारे में है। यह उन परिवारों के बारे में है जो उनके साथ खड़े हैं, ताकत और अदृट समर्थन का एक मूक स्तंभ हैं। इस दिन को मनाते हुए, आइए हम उन लड़ी गई लड़ाइयों और विजय को याद करें। आइए हम शहीद हुए वीरों का सम्मान करें और उन लोगों की अदम्य भावना को सलाम करें जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना जारी रखते हैं।

(लेखक पत्रकार है)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)



17 को व्यापारिक सम्मेलन में हजारों व्यापारियों को संबोधित करेंगी सीएम ममता

-सरकार चुनाव से पहले छोटे व्यवसायों व सभी वर्गों से समर्थन हासिल करना चाहती है

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 17 दिसंबर को व्यापारिक सम्मेलन 2025 में 12,000 से ज्यादा व्यापारियों को संबोधित कर सकती हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए 18 दिसंबर को एक व्यापार बैठक निर्धारित की गई है। यह व्यवसायी सम्मेलन 2025 इसलिए अहम है क्योंकि राज्य सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले छोटे व्यवसायों समेत सभी वर्गों से समर्थन हासिल करना चाहती है। पश्चिम बंगाल व्यापार संघ परिसंघ (सीडब्ल्यूबीटीए) के अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी मुख्य अतिथि होंगी। यह सीएम को हजारों छोटे व्यापारियों से जुड़ने का मंच प्रदान करेगा जो बंगाल की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि सीएम ममता व्यापार को आसान बनाने और जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकताएं तय करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों और सीमावर्ती व्यापार केंद्रों समेत सभी 23 जिलों के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की उम्मीद है।

दिसंबर माह में कर लें टैक्स रिटर्न से लेकर पैन तक सभी काम, नहीं तो होंगे परेशान



नई दिल्ली। दिसंबर माह में कई अहम वित्तीय और टैक्स संबंधी तारीखें करीब आ गई हैं। इन पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में दिक्कत हो सकती है। सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 की थी जो अब करीब आ रही है। यह उन करदाताओं के लिए राहत है जिनकी रिटर्न में ऑडिट और वित्तीय विवरण शामिल है। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार बनवाया था, तो इसे अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना 31 दिसंबर 2025 तक जरूरी है। लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड अप्रचलित हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश और आईटीआर फाइलिंग में परेशानी आएगी। विलंबित रिटर्न अगर आपने मूल समयसीमा मिस की थी, तो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेट फीस 5,000 तक (5 लाख रूपए से कम आय वालों के लिए 1,000 रूपए) और बकाया कर पर ब्याज देना होगा। संशोधित रिटर्न पहले फाइल किए गए रिटर्न में गलती सुधारने के लिए भी 31 दिसंबर तक मौका है। इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जिसमें 25 फीसदी से 50फीसदी तक अतिरिक्त दंड लगा सकता है। इसलिए दिसंबर 2025 अंतिम और सबसे फायदेमंद मौका है रिटर्न सुधारने या विलंबित रिटर्न फाइल करने का।

बीएनसीएपी क्रैश टेस्ट में मारुति ई-विटारा ने किया धमाका.....5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की

मुंबई।

भारत में गाड़ियों के लिए अब माइलेज के साथ सुरक्षा भी बढ़ा मानदंड बन चुका है, और इसी बीच मारुति सुजुकी ने बड़ा कारनामा किया है। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी 2025 मारुति ई-विटारा ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में धमाकेदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाई है। यह मारुति की चौथी कार है, जिसने बीएनसीएपी में इतनी शानदार रेटिंग हासिल की है। इसके पहले डिजायर, विक्टोरिस और इनविक्टो भी फुल 5-स्टार रेटिंग दे चुकी है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि यूरो एनसीएपी टेस्ट में यही ई-विटारा 4-स्टार स्कोर पर रकी थी, लेकिन भारत में हुए क्रैश टेस्ट में ई-विटारा ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है।

आम आदमी को आरबीआई दे सकती है राहत, बैठक में रेपो रेट पर होगा फैसला

5 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा फैसला सुनाएंगे

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार से शुरू हो गई है और ये बैठक 5 दिसंबर चलेगी। छह सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं। इस बैठक में रेपो रेट, बाजार में पैसे की स्थिति आने वाले समय में महंगाई का अनुमान और देश की आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पर फैसला लेंगे और इसके बारे में 5 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर फैसला सुनाएंगे। अगर इस बार रेपो रेट कम होता है तो इससे आम आदमी की जेब पर बोझ घट जाएगा। अक्टूबर वाली एमपीसी बैठक में आरबीआई की समिति ने रेपो रेट को

5.5फीसदी पर ही रखने का फैसला किया था यानी कोई बदलाव नहीं हुआ था। गवर्नर ने कहा कि महंगाई काफी कम हो गई है, इसलिए समिति को भरोसा है कि रेट अभी ऐसे ही रखना सही रहेगा। मतलब अक्टूबर में लोन की ईएमआई और कर्ज की किस्तों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पिछली बैठक में आरबीआई ने इस वित्त वर्ष के लिए महंगाई का लक्ष्य अनुमान घटाकर सिर्फ 2.6फीसदी कर दिया था, जो पहले 3.1फीसदी था यानी महंगाई पहले के हिसाब से काफी कम रहने वाली है। अगस्त की बैठक में भी अनुमान 3.7 फीसदी से घटाकर 3.1फीसदी किया गया था। मतलब

लगातार महंगाई के आंकड़े नीचे आ रहे हैं, जिससे आम आदमी को चीजों के दाम बढ़ने की कम चिंता होगी और ब्याज दरें भी जल्दी कम होने की उम्मीद है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर की आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक पर सबसे बड़ा असर महंगाई के बहुत तेजी से नीचे आने का है। घरेलू हालात अभी भी मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत के सामान पर 50फीसदी तक रेटिंग लगा रखा है और ट्रेड डील पर अभी भी बात चल रही है, ये बड़ी चिंता की बात है यानी अंतर से सब ठीक दिख रहा है, लेकिन बाहर का दबाव रेपो रेट घटाने के फैसले को प्रभावित कर सकता है।

एपिस इंडिया के शेयरधारकों की बह्ले-बह्ले..... हर 1 शेयर पर 24 फी शेयर देगी

एपिस इंडिया ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 तय

मुंबई ।

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। एफएमसीजी कंपनी एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को 24=1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने वाली है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फी शेयर बांटेगी। एपिस इंडिया ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 तय की है। कंपनी अपने निवेशकों को दूसरी

बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। एपिस इंडिया के शेयरों में पिछले कुछ साल में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 5500 प्रतिशत से ज्यादा उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया के शेयर 5593 प्रतिशत उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 20.25 रुपये पर थे। एपिस इंडिया के शेयर 1 दिसंबर 2025 को बीएसई में 1152.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 4376 प्रतिशत की जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले दो साल में एपिस इंडिया के शेयर 1303 प्रतिशत उछल गए हैं। इस साल 11 अप्रैल के बाद से कंपनी के शेयरों में 311

एसबीआई बैंक के शेयरों में 2025 की शुरुआत से अब तक 25 फीसदी की बढ़त ब्रोकरेज का अनुमान एसबीआई शेयर में तेजी आगे भी जारी रह सकती है

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों ने 2025 में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 2025 की शुरुआत से अब तक करीब 25 फीसदी की बढ़त दर्ज की है और इसने निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। एसबीआई शेयर में तेजी पिछले कुछ सालों से जारी है। साल 2023 में इस शेयर में 5फीसदी का उछल आया था तो 2024 इसने 23फीसदी रिटर्न दिया था। एसबीआई शेयर में तेजी आगे भी जारी रह सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का अनुमान है। यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए, एचएसबीसी, एक्सिस रिवे योरिटीज और नोमुरा ने एसबीआई शेयर को 'बाय' रेटिंग दी है। एसबीआई शेयर में आई तेजी की वजह बैंकिंग सेक्टर में मौलिक सुधार, आर्थिक स्थिरता और बेहतर क्रेडिट साइकल है। घरेलू और वैश्विक स्तर पर संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी भी एसबीआई की वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बने रहने, हाल में हुए जीएसटी स्लैब कटौती से उपभोक्ता खर्च में उछल की संभावना और भारतीय रिजर्व बैंक का 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.8फीसदी और 2027 में 6.6 फीसदी रहने का अनुमान बैंकिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा एसबीआई को होगा। फोर्ट कैपिटल के पराग ठक्कर का कहना है कि एसबीआई बैंक की 43 लाख करोड़ की लोन बुक भारत की कुल लोन बुक का करीब 23-24 फीसदी है, जबकि एसबीआई अभी भी 12-14फीसदी की गति से बढ़ रहा है और क्रेडिट कॉस्ट मात्र 50 बेसिस पॉइंट है।

अमेरिका में की 18 ट्रिलियन डॉलर निवेश की घोषणा, महंगाई में आएगी कमी

-ट्रंप का दावा- उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार हुआ

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार हुआ है। अमेरिका में अभी तक करीब 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश की नई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि महंगाई में कमी आ रही है और टेक्स को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं। यह सब अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के शोपेयर्स, कारोबारियों और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। एक लम्बी कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने पिछली सरकार की आर्थिक स्थिति की तुलना अपने कामकाज से की और कहा कि यह साल कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ

10 महीने में 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश कमिटेमेंट हासिल हुए हैं, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि देश में कंपनियों और निवेशकों का पैसा तेजी से आ रहा है, जिससे कंपनियों का पूंजी खर्च करीब 15 फीसदी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े टेक्स सुधार जिसे ट्रंप ने «वन बिग, ब्यूटिफुल बिल» कहा है। उसके कारण कंपनियों को 100 फीसदी खर्च घटाने की सुविधा मिली है और टिप, ओवरटाइम और सोशल सिक्योरिटी पर टेक्स हटा दिया गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी के मुताबिक इससे आम अमेरिकियों की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा और महंगाई से राहत मिलेगी। भारतीय-अमरीकी

ट्रंप के टैरिफ अटैक के कारण ट्रट रहा रुपया.....90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे

नई दिल्ली।

भारतीय रुपया बुधवार को 90 रुपये प्रति डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे पहुंच गया। व्यापार और निवेश के लिए डॉलर का निकलना और कंपनियों द्वारा आगे की कमजोरी से बचाव (हेजिंग) की होड़ ने मुद्रा पर दबाव बनाया है और इस तरह आठ महीने से जारी गिरावट को बढ़ा दिया है। रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5 प्रतिशत गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं बन गया है। भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय शेयरों पर 50 प्रतिशत तक के उच्च शुल्क (टैरिफ) के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है, इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों का आकर्षण कम हुआ है। वैश्विक स्तर पर पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह (पैसे की निकासी) से सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारों में भारत शामिल है।

इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 17 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। पोर्टफोलियो निवेश में कमजोरी के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी मंदी आई है, जिससे दबाव

और बढ़ा है। हाई अमेरिकी टैरिफ और सोने के आयात में तेज उछाल ने अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा (मचेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया है। साथ ही, घरेलू कंपनियों के विदेशी कर्ज और बैंकों में गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के जमा खातों से होने वाली डॉलर आपूर्ति भी कम हुई है। बैंकों और व्यापारियों का कहना है कि रुपये में गिरावट के हर चरण ने, विशेष रूप से आयातकों को तर्फ से, ताजा डॉलर मांग पैदा की है, जबकि निर्यातक डॉलर बेचने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। सार्थक पूंजी प्रवाह के अभाव में यह असंतुलन रुपये को असुरक्षित छोड़ रहा है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये में गिरावट की रफ्तार धीमी करने के लिए बीच-बीच में हस्तक्षेप किया है, लेकिन बैंकों का मानना है कि डॉलर की मांग का पैमाना और उसकी निरंतरता मुद्रा पर दबाव बनाए हुए है। आरबीआई के रुपये को सहारा देने के प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और फॉरवर्ड बाजार में शॉर्ट डॉलर पोजीशन के 5 महीने के उच्च स्तर (63.4 अरब डॉलर) पर पहुंचने में परिलक्षित होते हैं।

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली । भारतीय रुपया बुधवार को 25 पैसे की गिरावट के साथ ही अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 90.19 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज पहली बार 90 रुपये के स्तर के ऊपर पहुंच गया। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे नीचे आकर 90.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया। इससे वह और कमजोर हुआ है। अमेरिका के साथ व्यापार और पोर्टफोलियो में आई कमजोरी के साथ ही कारोबारी करार नहीं होने से भी बाजार पर दबाव पड़ा है। इससे पहले मंगलवार को रुपया इंट्रा-डे कारोबार में 89.94 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा और नियमित स्पॉट ट्रेडिंग के बाद इंटरबैंक ऑर्डर-मैचिंग प्लेटफॉर्म पर 90 प्रति डॉलर के स्तर से भी आगे निकल गया। भारतीय रिजर्व बैंक पांचवें कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे आया है।



शेयर बाजार हल्की गिरावट पर बंद

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही मुनाफावसूली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई, सेंसेक्स 31.46 अंक टूटकर 85,106.81 अंकों पर बंद हुआ। इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 46.20 अंक फिसलकर 25,986.00 अंकों पर बंद हुआ। आज ज्यादातर कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आये। वहीं गत दिवस भी बाजार नीचे आया था। बुधवार को सेंसेक्स की 30 में से केवल 10 कंपनियों के शेयरों में ही बढ़त रही। वहीं शेष सभी 20 कंपनियों के शेयर नीचे आये। इसी तरह निफ्टी की 50 में से केवल 13 कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए जबकि बची हुई सभी 37 कंपनियों के शेयर गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में

शामिल टीसीएस के शेयर सबसे ज्यादा 1.41 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए। जबकि बीईएल के शेयर आज सबसे ज्यादा 2.13 फीसदी नीचे आये। सेंसेक्स की अन्य कंपनियों में आज आईसीआईसीआई बैंक , एचडीएफसी बैंक , इंफोसिस, एक्सिस बैंक , टेक महिंद्रा , पावरग्रिड , एचसीएल टेक के शेयर बढ़त पर बंद हुए जबकि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा , टाइटन , एनटीपीसी, एसबीआई , अडाणी पोर्ट्स 1.13 , टाटा मोटर्स पैसंजर व्हीकल्स , बजाज फिनसर्व आदि के शेयर गिरावट पर बंद हुए। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार तेजी के साथ खुलने के बाद नीचे आये। सेंसेक्स हल्की तेजी के साथ ही 85,150 अंक पर खुला। खुलने के कुछ ही देर में इसमें गिरावट आने लगी। सुबह ये 197.27 अंक करीब 0.23 फीसदी फिसलकर 84,941 पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी सपाट रख के साथ तकरौबन 26,004



अंक पर खुला। यह 26 हजार के स्तर से नीचे आया है। सुबह यह 57.85 अंक करीब 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ ही 25,974 पर कारोबार कर रहा था। ज्यादातर एशियाई बाजार बुधवार को हरे निशान पर थे। वॉल स्ट्रीट में टेक्नोलॉजी शेयरों में उछाल और क्रिप्टोकॉर्सी में तेजी से एशियाई बाजारों में भी दिखा। जापान का निक्केई 225 0.76 फीसदी बढ़ा। हालांकि व्यापक टॉपिक्स 0.31 फीसदी गिरा।

दक्षिण कोरिया में कोस्पी 1.06 फीसदी ऊपर आया जबकि ऑस्ट्रेलिया के एस&एंडपी/एसएसएक्स में 200 0.32 फिसदी मजबूती आई।अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स एशिया के शुरुआती कारोबार में स्थिर रहे। प्रमुख अमेरिकी बेंचमार्क आज उछाल के बाद टिके रहे। डॉव 0.39 फीसदी बढ़ा, एस&एंडपी 500 में 0.25 फीसदी की बढ़त हुई और नैस्डेक 0.59 फिसदी उछला।

स्विगी अगले सप्ताह तक 10,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में

मुंबई। भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी अगले सप्ताह तक संस्थागत निवेशकों से 10,000 करोड़ (करीब 1.1 अरब डॉलर) तक जुटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि कंपनी फंड जुटाने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू कर सकती है। स्विगी ने शेयर बेचने के इस कदम को संभालने के लिए तीन बड़े बैंकों को चुना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निर्णय अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए सूत्रों ने अपना नाम गोपनीय रखने को कह दिया है। स्विगी के बोर्ड ने 7 नवंबर को यह योजना मंजूर की थी कि कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसेमेंट (क्यूआईपी) के जरिए अधिकतम 10,000 करोड़ जुटाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फंडिंग का सही समय और राशि में आगे बदलाव भी हो सकता है।



अडाणी एयरपोर्ट कारोबार को शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी में

कंपनी करीब 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी

नई दिल्ली। अडाणी ग्रुप अगले पांच साल में अपने सभी एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी करीब 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। इस निवेश के बाद अडाणी समूह के एयरपोर्ट हर साल 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि भारत में हवाई यात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है और कंपनी अपने एयरपोर्ट कारोबार को शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडाणी ग्रुप नवी मुंबई एयरपोर्ट में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। यह एयरपोर्ट 25 दिसंबर को शुरू हो सकता है। यहां नए यात्री टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, टैक्सीवे को बढ़ाया जाएगा और एक नई रनवे भी बनाई जाएगी ताकि ज्यादा उड़ानों को सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सके। इसके साथ ही कंपनी अहमदाबाद, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ाएगी। इन एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए और बेहतर सुविधाएं, ज्यादा स्पेस और सुचारू संचालन



के लिए जरूरी ढांचे में सुधार किए जाएंगे। इस पूरे विस्तार प्रोजेक्ट के लिए जो 15 बिलियन डॉलर की राशि चाहिए, उसमें से करीब 70 फीसदी पैसा कर्ज के रूप में जुटाया जाएगा। कंपनी यह कर्ज अगले पांच साल के दौरान लेगी। बाकी का पैसा कंपनी अपनी ओर से लगाएगी जिसे इक्विटी कहा जाता है। इस तरह बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर सुधार का खर्च पूरा किया जाएगा। भारत में अगले वर्षों में हवाई यात्रा काफी तेजी से बढ़ने वाली है। उम्मीद है कि 2030 तक देश में हर साल 300 मिलियन यानी तीस करोड़ लोग उड़ान भरेंगे। अडाणी ग्रुप अपनी क्षमता को 200 मिलियन तक बढ़ाकर इस पूरे विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे कंपनी की फकड़ भारतीय विमानन बाजार पर मजबूत होगी और उसकी एयरपोर्ट यूनिट का आईपीओ और भी आकर्षक बन जाएगा। इस बड़े प्लान में नवी मुंबई एयरपोर्ट की 20 मिलियन यात्रियों की क्षमता और गुवाहाटी एयरपोर्ट की 11 मिलियन क्षमता शामिल नहीं है। मतलब ये दोनों एयरपोर्ट पहले से अलग गिने गए हैं, और जो नया विस्तार हो रहा है वह इस अलग हट कर है।

रायपुर में 'किंग कोहली' का जलवा, 53वें शतक से रचा इतिहास, गायकवाड़ ने भी दिखाया दम



रांची (एजेंसी)। विराट कोहली ने बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे के दौरान अपना 53वां वनडे शतक लगाया। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक भी था। पहले वनडे में, कोहली ने रांची में भारत की 17 रनों की जीत में 120 गेंदों पर 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रन बनाए थे।

37 वर्षीय दिग्गज बल्लेबाज ने 90 गेंदों में अपना 53वां वनडे शतक पूरा किया। कुल मिलाकर, यह भारतीय महान का 84वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। वह सर्वाधिक

अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में महान सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हैं। उन्होंने रतुराज गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिए 195 रनों की शानदार साझेदारी की। रतुराज गायकवाड़ ने भी अपना पहला वनडे शतक जड़ा। रायपुर में इस स्टार बल्लेबाज ने 77 गेंदों में शतक पूरा किया।

उन्होंने 83 गेंदों पर 105 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक जड़ा। कोहली की तरह, गायकवाड़ ने भी स्ट्राइक रेट से समझौता नहीं किया और बीच में कुछ बेहतरीन शॉट खेलें। मैच के 36वें ओवर में मार्को जेनसन ने उन्हें आउट कर दिया। गौरतलब है कि दोनों ने

195 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत दूसरे वनडे में बढ़त बना पाया। वे बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे और इसी के लिए केएल राहुल को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है।

कोहली ने 93 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रन बनाए। इससे पहले, यशस्वी जायसवाल (22) और रोहित शर्मा (14) सस्ते में आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बावुमा और महाराज को पहले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन इस मैच में दोनों की वापसी हुई है।

हार्दिक टी20 में 300 छक्के लगाने वाले धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी बने



मुम्बई (एजेंसी)। अनुभवी ऑलराउंडर पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में एक अहम रिकार्ड अपने नाम किया। हार्दिक ने पंजाब के खिलाफ एलीट ग्रुप सी मैच में अपनी 42 रनों की पारी में चार छक्के लगाने के साथ ही टी20 क्रिकेट में अपनी 300 छक्के पूरे कर लिए। इसी के साथ ही हार्दिक भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरी खिलाड़ी बन गये हैं। यह उपलब्धि हार्दिक की पावर-हिटिंग क्षमता और लगातार सुधारते प्रदर्शन को दर्शाती है। हार्दिक बड़ौदा की ओ से इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। पंजाब के

खिलाफ मैच में पहला छक्का लगाते ही उनके 300 छक्के पूरे हो गये। हार्दिक का यह प्रदर्शन दिखाता है कि अब वह फिट हो गये हैं। हार्दिक अब भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में बिना एक भी शतक लगाए 300 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं। उनका टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर 91 रन है, और अब तक वे 268 पारियों और 309 मैचों में कुल 303 छक्के उनके नाम हैं। यह उपलब्धि बताती है कि हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक दमदार फिनिशर और पावर-हitter भी हैं। वही धोनी ने 355 टी20 पारियों में बिना शतक लगाए 350 छक्के लगाए थे।

आईपीएल 2026 नीलामी : इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पर होगी पैसों की बारिश, बन सकते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे चर्चित नामों में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार वह ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं। टीम इंडिया के सीनियर स्पिन्नर रविचंद्रन अश्विन ने भी भविष्यवाणी की है कि ग्रीन इस सीजन में बड़ी बोली हासिल कर सकते हैं।

अश्विन ने बताया ग्रीन को 'जैकपॉट खिलाड़ी'

अश्विन के अनुसार, इस साल आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्फोटक विदेशी ऑलराउंडर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में फ्रेंचाइजियां तेज गेंदबाजी करने वाले और मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की तलाश में सीधे कैमरन ग्रीन पर नज़र टिकाएंगी। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'कैमरन ग्रीन को कह दो कि सिडनी हार्वर के पास 4-5 एकड़ जमीन बूक कर लें। इस बार ऑक्शन में न रसेल हैं, न मैक्सवेल।

ऐसे में ग्रीन और लियाम लिविंगस्टोन दोनों के लिए बड़ा जैकपॉट तैयार है।'

वर्गों है ग्रीन की वैल्यू इतनी ज्यादा?

कैमरन ग्रीन इस समय दुनिया के सबसे 'कम्प्लीट' टी20 खिलाड़ियों में गिने जाते हैं- धाकड़ मिडिल-ऑर्डर हिटर, 140+ किमी/घं की रफ्तार से गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, युवा और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट। 2025 में उनके लगातार उत्कृष्ट टी20 प्रदर्शन ने उनके मूल्य को और बढ़ा दिया है। ग्रीन ने 40+ की औसत और तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो टी20 में बेहद दुर्लभ है।

आईपीएल में अब तक का प्रदर्शन

सिर्फ दो सीजन में ही कैमरन ग्रीन ने अपना दम दिखा दिया है: 29 मैच, 707 रन, 1 शतक, 16 विकेट। ग्रीन ने प्रेशर सिचुएशन में भी मैच जिताते वाली पारियां खेली हैं और जरूरत के हिसाब से आक्रामक या एंकर दोनों भूमिकाएं निभाई हैं। यही वजह है कि कई टीमों उन्हें अपने 'ड्रीम साइनिंग' के रूप में देख रही हैं।

हार्दिक पांड्या की वापसी, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी: दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित

मुम्बई (एजेंसी)। बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने 9 दिसंबर से कटक में शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20आई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे, टीम में वापसी कर चुके हैं। पांड्या सितंबर में एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ भारत के सुपर फोर मुकाबले के बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20आई खेलेंगे। पांड्या चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल और ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौर से चूक गए थे।

हाल ही में, भारतीय ऑलराउंडर पांड्या ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलते हुए अपनी फिटनेस साबित की। रिकू सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया की टी20आई के लिए टीम का हिस्सा थे, को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20आई श्रृंखला के लिए टीम से



बाहर कर दिया गया है। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने वाले शुभमन गिल को चोट के कारण दूसरे टेस्ट और तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहने के बाद टीम में शामिल किया गया है।

हालांकि, गिल को घरेलू मैदान पर प्रोटियाज के खिलाफ पांच मैचों की टी20आई सीरीज में भाग लेने के लिए बीसीसीआई के सेंट ऑफ एक्ससीलेंस (सीआई) से अपनी फिटनेस मंजूरी लेनी होगी। भारतीय टीम पांच मैचों की

सीरीज का पहला टी20आई 9 दिसंबर को कटक में प्रोटियाज के खिलाफ खेलेगी। मुलनपुर 11 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20आई की मेजबानी करेंगे। तीसरा टी20आई 14 दिसंबर को धर्मशाला में और चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाएगा। अहमदाबाद 19 दिसंबर को सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच की मेजबानी करेंगे। इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सफाया कर दिया था। भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे चल

रहा है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजु सेमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

केकेआर को खलेगी रसेल की कमी, बेहद प्रभावशाली रहे हैं आंकड़ें



जैम्बा। वेस्टइंडीज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अब आईपीएल में खेलते नजर नहीं आयेगे। रसेल आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) की ओर से खेलते थे और उनके आंकड़े काफी प्रभावी रहे हैं। ऐसे में उनके नहीं होने की कमी टीम को खलेगी। इसी कारण टीम के मालिक शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर लंबा और भावुक संदेश लिखकर उनकी सेवाओं को सलाम किया है। रसेल ने आईपीएल के 140 मुकाबलों की 115 पारियों में कुल 2651 रन बनाये हैं। इनका स्ट्राइक रेट 174.17 रहा है। उन्होंने 186 चौके, 223 छक्के लगाये हैं और गेंदबाजी के दौरान 123 विकेट लिए हैं। रसेल साल 2014 से ही केकेआर में शामिल रहे और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी व कसी हुई गेंदबाजी से मैच विजेता साबित हुए। 174.17 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट की बदौलत वह टी 20 के सबसे खतरनाक फिनिशर बने। उन्होंने अपने करियर में 12 अर्धशतक, 186 चौके और 223 छक्के लगाये। केवल बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी रसेल ने अपनी ताकत दिखायी। उन्होंने आईपीएल में कुल 123 विकेट हासिल किए और कई अवसरों पर टीम को परेशानी से निकाला। उनसे इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण ही केकेआर की टीम में वह गेम-चेंजर के तौर पर भी जाने जाते हैं। रसेल अब केकेआर में पावर कोच के तौर पर दिखेंगे। इसी को देखते हुए शाहरुख ने कहा कि तुम हमेशा हमारे योद्धा रहोगे। अब पावर कोच के रूप में टीम के खिलाड़ियों को अपनी ताकत, अनुभव और सफलता के राज सिखाओ।

विराट कोहली घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार वापसी के लिए तैयार, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली दोनों ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलने की पुष्टि कर दी है। यह फैसला न केवल घरेलू क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दिल्ली की टीम को भी बड़ा फायदा देगा। पंत लगभग सात साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे, जबकि कोहली 14 साल बाद फिर से दिल्ली की ओर से लिस्ट-ए मुकाबले खेलते नजर आएंगे। दोनों के खेलने से दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा।

ऋषभ पंत की धमाकेदार वापसी तय

सूत्रों के अनुसार, ऋषभ पंत ने DDCA को अपनी उपलब्धता की औपचारिक पुष्टि कर दी है। 2018 के बाद पहली बार पंत विजय हजारे ट्रॉफी में दिखाई देंगे। पंत ने 2015 से अब तक दिल्ली के लिए 19 लिस्ट-ए मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 531 रन बनाए। उनकी पारी में एक शतक, दो अर्धशतक और 109.48 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट शामिल है। पंत की वापसी खास इसलिए भी है क्योंकि उनकी आक्रामक बैटिंग शैली दिल्ली के लिए मैच-विनिंग साबित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने 31

ODI मुकाबलों में 871 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार सेंचुरी और पांच फिफ्टी शामिल हैं। उनकी फिटनेस और फॉर्म को देखते हुए दिल्ली के लिए यह एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

विराट कोहली भी विजय हजारे ट्रॉफी में उतरने को तैयार

35 वर्षीय भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली ने भी DDCA को टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता का भरोसा दिला दिया है। कोहली अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ODI फार्मेट में विशेषज्ञ बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। 2010 के बाद यह पहला मौका होगा जब कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की जर्सी पहनकर उतरेंगे।

2010 में खेले गए पांच मैचों में कोहली ने 45.80 की औसत से 229 रन बनाए थे और दो अर्धशतक भी लगाए थे। उनकी मौजूदा फॉर्म शानदार है और वह घरेलू गेंदबाजों पर हावी होते नजर आ सकते हैं। कोहली कर्नाटक के मैदानों पर दिल्ली के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इस बार दिल्ली के कोर्ट में कोई होम ग्रुप मैच नहीं है।

दिल्ली के अभियान को मिलेगा बड़ा फायदा

पंत और कोहली के आने से दिल्ली का लाइन-अप बेहद प्रभावशाली हो जाएगा। दोनों खिलाड़ी बड़े मैचों में टीम का मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के



लिए प्रेरणादायक होगी और टीम संयोजन को भी संतुलित बनाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी के सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले 8 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे, जिससे पंत और कोहली दोनों

के पास अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल से पहले पर्याप्त गेम टाइम मिलेगा। 11 जनवरी से भारत-न्यूजीलैंड की ODI सीरीज शुरू होगी, जहां कोहली को फिर एक्शन में देखा जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

यीशु पर बनी रूबेन्स की दुर्लभ पेंटिंग 27 लाख डॉलर में बिकी

पेरिस, एंजेंसी। बारोक काल के महान चित्रकार पीटर पॉल रुबेन्स की एक लंबे समय से खोई पेंटिंग वर्सलीज में नीलामी के दौरान 27 लाख डॉलर में बिकी। ईसा मसीह (यीशु) को सुली पर चढ़ाए जाने का दृश्य बताने वाली यह पेंटिंग बार सदी से अधिक समय बाद हाल में पेरिस के एक निजी टाउनहाउस में मिली थी। यह एक फ्रांसीसी संग्रह का हिस्सा थी। विशेषज्ञ निल्स ब्यूटनर ने कहा, यह एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिसमें ईसा मसीह के पार्श्व-घाव से रक्त और पानी बहते दिखाया है। रुबेन्स ने इसे एक बार में बनाया था।

कराची : तेज रफ्तार स्पीडबोट की टक्कर में यात्री नाव डूबी, 2 मरे

कराची , एंजेंसी। पाकिस्तान के कराची के मनोरा के पास समुद्र में रविवार शाम एक निजी स्पीडबोट की टक्कर एक यात्री नाव से हो गई। इस हादसे में एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हुए हैं। डीआईजी सैयद असद रजा ने बताया कि शाम 6 :30 बजे जब यह टक्कर हुई तब नाव मनोरा बीच से जेटी नंबर 1 की ओर जा रही थी। टक्कर से नाव पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसमें चार परिवारों के कुल 22 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान नौसेना और कराची पोर्ट ट्रस्ट ने उन्हें बचाया। रजा ने कहा कि दो घायल लड़कियों की हालत नाजुक बनी हुई है।

तस्करी के शक में ईरान में दो द. कोरियाई नागरिक गिरफ्तार

सियोल, एंजेंसी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि ईरान में तस्करी के शक में दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान में उनका राजनयिक मिशन ईरानी अधिकारियों के साथ संघर्ष में है। मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता दी जाएगी। हालांकि, मंत्रालय ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पेशा या आरोपों की सटीक प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।

चीनी जल विद्युत प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप

बीजिंग, एंजेंसी। चीन के फुजियान प्रांत में बन रहा एक प्रमुख हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट योंगआन पावर स्टेशन गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों के कारण जांच के घेरे में है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने बताया कि 7.5 अरब युआन (1.06 अरब अमेरिकी डॉलर) की इस परियोजना में घटिया सामग्री और लापरवाही से निर्माण करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि इसके निचले जलाशय (लोअर रिजर्वायर) में गंभीर गुणवत्ता दोष हैं। यह लोअर रिजर्वायर बिजली उत्पादन का मुख्य केंद्र है।

बलूचिस्तान : अर्धसैनिक बल मुख्यालय पर हमले में 3 मौतें

इस्लामाबाद, एंजेंसी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमले की कोशिश को सुरक्षाकर्मियों ने नाकाम बताते हुए प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के तीन चरमपंथियों को ढेर कर दिया। अर्धसैनिक बल का दावा है कि चगाई जिले के नोकुंडी करबे में फ्रंटियर कोर (एफसी) मुख्यालय पर आत्मघाती हमले के बाद चरमपंथियों ने वहां घुसने का प्रयास किया। इस पर त्वरित जवाबी कार्रवाई की गई। प्रवक्ता ने बताया कि कम से कम छह हमलावरों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। इस बीच मुख्यालय में घुसने में कामयाब रहे तीन आतंकियों को मार गिराया गया। सुत्रों के अनुसार, बीएलए चरमपंथियों ने पंजगुर के गुरमाकन क्षेत्र में एक अन्य एफसी चौकी को भी निशाना बनाया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। माना जा रहा है इस घटना में कई हमलावर मारे गए लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक, एक हमलावर ने मुख्य द्वार पर खुद को उड़ा लिया, जिसके कारण कई संरक्षक हमलावर शिविर में घुस गए। कई घंटे तक झड़पें जारी रहीं।

सिडनी में चल रहे अंतरराष्ट्रीय बाल शोषण रैकेट का भंडाफोड़

सिडनी, एंजेंसी। सिडनी में पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो ऑनलाइन फैलाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बाल शोषण चिरोह से जुड़ा था, जिसके वीडियो में खतरनाक रस्मों और शैतानी प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने इस कार्रवाई को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया है।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने ऑनलाइन एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर चल रही संदिग्ध गतिविधियों की जांच के दौरान इस नेटवर्क की पहचान की। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट जेन डोहर्टी ने बताया कि यह सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे वीडियो शामिल थे जिनमें बच्चों को शैतानी अनुष्ठानों से जुड़े प्रतीकों

और रिवाजों का इस्तेमाल करते हुए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह सामग्री ‘अत्यंत भयावह’ है और बातचीत में भी ऐसे संकेत मिले जिससे पता चलता है कि आरोपी इसी तरह की क्रूर सामग्री साझा करते थे।

कैसे पकड़े गए आरोपी : पिछले गुरुवार को सिडनी में कई स्थानों पर छापे मारे गए और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें हजारों वीडियो संग्रहित थे। यह सामग्री ऐसे बच्चों की थी जिनकी उम्र कुछ महीनों से लेकर 12 साल तक बताई गई है। पुलिस का कहना है कि यह सबूत दिखाते हैं कि आरोपी एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा थे, जो ऑनलाइन बच्चों पर अत्याचार से जुड़े वीडियो साझा करता था।

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ी : पुलिस ने बताया कि यह नेटवर्क अलग-

पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगाई:रैली-जुलूस निकालने पर रोक

प्रदर्शन की धमकी के बाद फैसला, इमरान से मिलने की मांग कर रही पार्टी

इस्लामाबाद, एंजेंसी। पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों और देश में अशांति फैलने के डर के बीच आया है। इसके तहत 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने, 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। डिटी कमिश्नर डॉ. हसन वकार ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है।

आदेश में हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नफरत भरे भाषण देना, पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करना, दो लोगों के एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह रोक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रावलपिंडी (अड्डियाला जेल) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के फैसले के बाद आया है।

दावा- संदिग्ध संगठन कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में : आदेश में कहा गया है कि जिला खुफिया समिति ने रिपोर्ट दी है कि कुछ संगठन



और तत्व बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करके कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की फिराक में हैं। ये लोग संवेदनशील ठिकानों, सरकारी इमारतों और चुनिंदा जगहों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं।

पीटीआई नेता बोले- कोर्ट आदेश को लागू करने में नाकाम, इमरान से नहीं मिला पा रहे : पीटीआई नेता असद कायसर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे और फिर अपनी धरना अड्डियाला जेल ले जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘प्रदर्शन करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोर्ट अपने आदेश को लागू करने में नाकाम रही है और जेल प्रशासन भी कोर्ट के आदेशों का पालन

करने को तैयार नहीं है।’ पिछले हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने जेल के बाहर धरना दिया था, जब उन्हें आठवीं बार इमरान खान से मिलने से रोका गया। इसी तरह, खान के परिवार के सदस्यों को कई हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

न्याय राज्य मंत्री बोले- खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी : इससे पहले पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार को कहा, ‘पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हातहत बहुत खराब हो चुकी है।’ पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। जियो न्यूज के मुताबिक मलिक ने कहा, ‘खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल

अफरीदी वहां की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं। वह न तो केंद्र सरकार से कोई तालमेल रख रहे हैं और न ही जरूरी जगहों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं।

सेना के आदेश पर अफरीदी को पुलिस ने पीटा था : इमरान खान का समर्थन करने रावलपिंडी की अड्डियाला जेल पहुंचे खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने 27 नवंबर को सड़क पर गिराकर पीटा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम सोहेल अफरीदी पर हमलों की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई। अफरीदी गुरुवार को जिस समय जेल पहुंचे थे वहां भारी सुरक्षा तैनात थी और पीटीआई समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उनके पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का-मुक्की के दौरान पुलिसकर्मियों ने सीएम को लात-घुंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। अफरीदी ने बड़े विरोध-प्रदर्शन की धमकी दी थी अफरीदी का कहना है कि सरकार को इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठे सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे।

मादुरो को ट्रंप की चेतावनी, फोन कर कहा- देश छोड़ दें, अमेरिका-वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ा

वांशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर खतरे की रेखा पार करता दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात की और उन्हें तीखा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि वह तुरंत देश नहीं छोड़ते, तो हालात और गंभीर हो जाएंगे। ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब कैरौबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ चुकी है और दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने मादुरो से साफ कहा, ‘आप खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन आपको अभी देश छोड़ना होगा।’ अमेरिका ने मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस और उनके बेटे को

सुरक्षित रास्ता देने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव मादुरो के कई शीर्ष सहयोगियों तक भी बढ़ाया गया था। लेकिन मादुरो ने इसे ठुकरा दिया। वेनेजुएला की तरफ से दो मुख्य मांगें रखी गईं। पहली, मादुरो और उनके करीबी सफल के लिए वैश्विक माफी और दूसरी, वेनेजुएला की सेना पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार। अमेरिका ने इन दोनों मांगों को मंजूर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बातचीत पूरी तरह टूट गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा संकेत : ट्रंप ने रविवार को स्वीकार किया कि उन्होंने हाल ही में मादुरो से बात की है, लेकिन उन्होंने बातचीत की प्रकृति पर कोई जानकारी देने से मना कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि वेनेजुएला का एयरस्पेस पूरी

तरह बंद माना जाए। उनकी इस घोषणा के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया। फ्लाइटराइड24 के मुताबिक, देश के ऊपर एक भी विदेशी विमान नहीं देखा गया। कुछ एयरलाइंस ने वैकल्पिक रास्ते अपनाए, जबकि कई ने सेवाएं रोक दीं।

शर्तों की वजह से अटका समाधान : रिपोर्ट के अनुसार, कल 16 नवंबर को हुई थी। इसमें मादुरो ने दो बड़े आश्वासन मांगे पहला, कि उन्हें और उनकी टीम को किसी भी मौजूदा आरोपों से वैश्विक स्तर पर पूरी तरह माफी मिले। दूसरा, वेनेजुएला की सेना पर उनका नियंत्रण बना रहे, भले ही भविष्य में देश में स्वतंत्र चुनाव हों। अमेरिका ने इन दोनों शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि

मादुरो को पद तुरंत छोड़ना होगा। बताया गया कि मादुरो सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से दोबारा बातचीत की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मादुरो और उनकी शासन व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा दबाव बना रही है।

बातचीत टूटने के बाद अमेरिका ने अपने शब्दों के साथ-साथ अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सैन्य अभियान जल्द ही जमीन पर शुरू हो सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी जहाज और लड़ाकू विमान कैरैबियन में सक्रिय दिखाई दिए। अमेरिका ने दावा किया है कि वेनेजुएला की जमीन से ड्रग तस्करी बढ़ रही है, जिससे अमेरिका में 100000 लोगों की मौत हुई।

बांग्लादेश लौटने की तैयारी में बेटा तारिक रहमान, 15 साल से लंदन में हैं निर्वासित



ढाका, एंजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष 80 वर्षीय बेगम खालिदा जिया की तबीयत गंभीर बनी हुई है। ताजा अपडेट के अनुसार उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेशन पर रखा गया है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल में पुलिस और विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) की तैनाती की गई है। दूसरी ओर अब खालिदा जिया की ज्यादा गंभीर होती तबीयत को देखते 15 साल से लंदन में निर्वासन में रह रहे उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बताया कि खालिदा जिया के बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, जो पिछले 15 साल से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं, जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगे। तारिक नए बांग्लादेशी पासपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कारण है कि रहमान अस्थायी सरकार द्वारा दिए गए एक बार यात्रा

पास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते।

‘चुनाव को लेकर भी पार्टी में हलचल : बता दें कि अगले साल फरवरी में होने वाले बांग्लादेशी आम चुनाव को लेकर भी देशभर में हलचल तेज है। ऐसे में बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का स्वास्थ्य खराब होना, पार्टी के लिए अच्छ संकेत नहीं माना जा रहा है। ऐसे में बीएनपी की शीर्ष बैठक में पार्टी ने चुनावी रणनीति और वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की। बीएनपी, अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बदलते राजनीतिक परिदृश्य में फिर से मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। बड़ाई गई अस्पताल की सुरक्षा उधर, खालिदा जिया की बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार सुबह 2 बजे के करीब अस्पताल के मुख्य गेट पर बैरिकेड लगाई गई और दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मध्याह्न से विशेष सुरक्षा बल के चार सदस्य अस्पताल में पहुंचे और लगभग तीन घंटे तक सुरक्षा निरीक्षण किया।

एसआईआर : उन्नाव में एक घर से थे 45 मतदाता, सत्यापन के बाद बचे मात्र 3 वोटर

उन्नाव (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले में यह मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कप मच गया। कमलेश कुमार, आशीष और माधुरी देवी, जो अपने दो नाबालिग बच्चियों के साथ रहते हैं। इन तीनों ने अपना एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कर दिया था। बाकी 42 लोगों का नाम, जो उसी पते पर दर्ज हैं, कौन हैं और कहाँ रहते हैं, यह अब तक स्पष्ट नहीं है।सदर तहसील के पूरन नगर मोहल्ल के 57 नंबर घर के पते पर वोटर लिस्ट में 45 लोगों के नाम दर्ज थे। जब क्षेत्र के बीएलओ राजीव त्रिपाठी निर्वाचन निर्वाचक नामावली 2025 की वोटर लिस्ट लेकर एसआईआर वोटर सत्यापन के लिए गए, तो उन्होंने पाया कि इस घर में केवल तीन लोग मौजूद हैं।।एडीएम सुशील कुमार गौड़ ने कहा कि यह मामला निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की सटीकता पर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और पूरी तरह जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। मामले के सामने आने के बाद एडीएम ने बताया कि मामले की टीम बनाकर जांच कार्रवाई जारी रही है। उन्होंने कहा कि एआरओ (असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर) को टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्नाव जिले में कई फैक्ट्रियां भी हैं, संभव है कि किसी की जानकारी गलती से इस पते पर दर्ज हो गई हो। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यात्री की तबीयत बिगड़ी... तिरुवनंतपुरम जा रहे विमान को मंगलुरु में उतारा गया

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। यात्री के अवाक स्वास्थ्य खराब होने के कारण तिरुवनंतपुरम जा रहे एयर इंडिया एयरसास के विमान को मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। सोमवार देर रात तिरुवनंतपुरम जा रहे विमान में एक लगभग 35 वर्षीय यात्री को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई। विमान के चालक दल ने तुरंत मंगलुरु हवाई अड्डे के संचालन नियंत्रण केंद्र को सूचित किया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए और चिकित्सा दल, सीआईएसएफ, आब्रजन और सीमा शुल्क विभाग के साथ समन्वय किया। विमान के उतरते ही हवाई अड्डे के चिकित्सा कर्मियों ने यात्री की स्थिति का आकलन किया और उन्हें तत्काल शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री के रिश्तेदार भी उनके साथ विमान से उतरे। चालक दल की समय पर मदद से यात्री को स्थिर करने में मदद मिली। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद, विमान देर रात दो बजकर पांच मिनट पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुआ। एयरलाइन एक प्रवक्ता ने इस समन्वित प्रतिक्रिया को हवाई अड्डे की तत्परता और यात्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। यह घटना दर्शाती है कि विमानन और हवाई अड्डा अधिकारी किस तरह चिकित्सा संबंधी आकस्मिकताओं से प्रभावी ढंग से निपटते हैं।

दो कॉलेजों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्कॉड ने ली तलाशी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली युनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद कैपस में तलाशी शुरू की गई। बता दें इन दो कॉलेजों में रामजस कॉलेज और देश बंधु कॉलेज का नाम सामने आया है। कॉलेजों को यह धमकी मेल के जरिए दी भेजी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों कॉलेजों के कैपस में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और बम स्कॉड टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। अधिकारी फिलहाल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि यह धमकी महज एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई वास्तविक मंशा। यह पहली बार नहीं है जब राजधानी के शैक्षणिक संस्थानों को ऐसी धमकियां मिली हैं। पिछले महीने 18 नवंबर को भी दिल्ली के द्वारका और प्रशांत विहार स्थित दो स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके अलावा साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला कोर्ट समेत तीन अदालत परिसरों को भी धमकी भरे संदेश मिले थे। उन सभी मामलों में भी गहन जांच के बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी और धमकियां फर्जी निकलीं। इन घटनाओं के कारण सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और वर्तमान मामले को भी पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है।

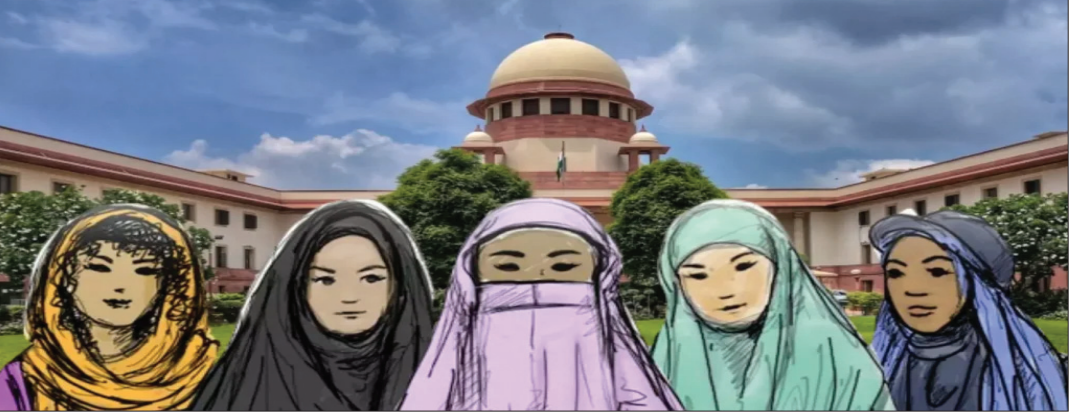
इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में तकनीकी खराबी से हड़कप... रात भर से परेशान हो रहे यात्री

हैदराबाद (एजेंसी)। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बीती रात से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में तकनीकी खराबी ने हड़कप मचाया हुआ है। तकनीकी समस्या के कारण मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली के लिए उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। इसके चलते करीब 1000 यात्री एयरपोर्ट पर लंबी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी यात्रा योजनाएं बाधित हो गई हैं। विशेष रूप से बैंगलुरु जाने वाली उड़ानें ज्यादा प्रभावित हुईं। मंगलवार -रात 2 बजे निर्धारित एक उड़ान को रनवे पर ही दो घंटे तक रोकया गया। बदती चिता और तनाव के बीच यात्रियों को विमान से उतरकर एयरपोर्ट टर्मिनल में इंतजार करने के लिए कहा गया। सबसे बड़ी परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जिन्हें विदेश जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी या ज़िंदा इंटरव्यू के लिए विभिन्न शहरों का सफ़र तय करना था। एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो कर्मचारी तकनीकी गड़बड़ी पर संतोखजनक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। एक यात्री ने बताया, 'हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। खाने-पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं हुई।' इंडिगो एयरलाइंस प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी खराबी की समस्या सामने आई है और जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की और उन्हें हर संभव सहानुभूता देने का आश्वासन दिया। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह घटना देश के सबसे बड़े विमानन संचालकों में से एक के लिए चिंता का विषय है। इंडिगो को हाल के महीनों में तकनीकी विश्वसनीयता को लेकर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है।



मुस्लिम महिला को तलाक दिया है तो निकाह में मिला सामान और उपहार भी लौटाना पड़ेगा: कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को निकाह के समय अपने मायके से लाया गया पूरा सामान, सोना-चांदी, नकदी तथा रिश्तेदारों-दोस्तों से मिले सभी उपहार वापस लेने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। न्यायमूर्ति सजिव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा कि इन वस्तुओं को महिला की निजी संपत्ति माना जाएगा और तलाक के बाद इन्हें वापस करना बाध्यकारी होगा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की नई एवं व्यापक व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि इस धारा को केवल सिविल विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सविधान द्वारा प्रदत्त लैंगिक समानता, गरिमा और आर्थिक स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप समझा जाना चाहिए। पीठ ने 2001 के डैनियल लतीफो बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून का मूल उद्देश्य तलाक के बाद मुस्लिम महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर



बनाना है। मामला कोलकाता की एक तलाकशुदा महिला का था, जिसने अपने पूर्व पति के खिलाफ 1986 के कानून के तहत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के दावे को पूरी तरह न्यायोचित मानते हुए पूर्व पति को 17,67,980 रुपये छह हफ्तों के अंदर महिला के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कलकत्ता हाई

कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया, जिसमें महिला के दावे को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को महज सिविल वाद की तरह देखा और निकाहनामे में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर सबूतों की गलत व्याख्या की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने कानून के सामाजिक न्याय के उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया और संवैधानिक

मूल्यों से विमुख निर्णय दिया।यह फैसला देश भर में लाखों तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की खबर है। अब वे न सिर्फ मेहर व गुजारा भत्ता, बल्कि शादी में अपने मायके से लाया सामान और मिले सभी उपहार कानूनी रूप से वापस प्राप्त कर सकेंगी। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे लैंगिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

यदि वक्फ की संपत्तियां छीनी गईं, तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे: चौधरी

–कबीर के बयान पर कहा मस्जिद पवित्र स्थान है, राजनीति का माध्यम नहीं

कोलकाता (एजेंसी)। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को लागू करने की स्वीकृति देने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी सरकार में मंत्री और जाँमिया उल्लेमा-ए-हिंद पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लह चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि वक्फ की संपत्तियां छीनी गईं, तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। चौधरी ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी कगरे में बैठकर बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन क्या कोई गांव में जाकर लोगों से कह सकता है कि वक्फ संपत्ति अब उनकी नहीं रही? यह फैसला मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। हम इसे नके नीतय से उठाना क्या कदम नहीं मानते। का मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा

कि राज्य सरकार ने महीनों तक इस कानून को लागू करने से इनकार किया था, लेकिन पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के निर्देश मानते हुए राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पहले कुछ और सोच रही थी। अब सीएम ममता बनर्जी कुछ और सोच रही होंगी। वक्फ संपत्तियां बेहद अहम हैं। आगे क्या होगा, हम नहीं जानते, लेकिन लड़ाई लंबी और कठिन होगी। हमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण वाले बयान पर चौधरी ने कहा कि यह कदम बेहद संवेदनशील है और इससे अखातिफ तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिज्ञ नेता ने ऐसी बातें कही हैं, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठें हैं। हम कोई भी काम बिना सोचे-समझे नहीं करते। मस्जिद एक पवित्र स्थान है, राजनीति का माध्यम नहीं।

महापुरुषों की जयंती-पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े स्थलों पर नहीं जाएंगी मायावती

–बसपा सुप्रीमो ने कहा– उनकी सुरक्षा के चलते लोगों को होती है परेशानी

कोलकाता (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने महापुरुषों की जयंती-पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े स्थलों पर न जाकर अपने निवास स्थान पर या पार्टी कार्यालय में ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की छह दिसम्बर को पुण्यतिथि है। इसके पहले बुधवार को उन्होंने एक पोस्टर में कहा कि महापुरुषों की जयंती-पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े स्थलों पर जाने पर उनकी (यानी मायावती) की सुरक्षा के व्यवस्था के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने यह तय किया है कि अब उन स्थलों पर नहीं जाएंगी। निवास स्थान या कार्यालय पर ही श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे ताकि बसपा के नेतृत्व में उनके आत्म सम्मान और स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करके मंजिल की ओर आगे बढ़ा जा सके।

मायावती ने पोस्ट में लिखा-‘जैसा कि सर्वविदित है कि यूपी में मेरे नेतृत्व में चार बार बनी बसपा सरकार के दौरान ‘बहुजन समाज’ के समय-समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं व



महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायण गुरु, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं मास्टर काशीराम आदि को कई रूपों में भरपूर आदर-सम्मान दिया गया है, जिनकी जातिवादी पाँटियों की रही सरकारों में यह हमेशा उपेक्षा की गई व उनका तिरस्कार भी किया जाता रहा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि इस क्रम में परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर, यूपी में पार्टी के लोग व उनके अनुयायी

मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसम्बर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में और पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखण्ड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे और उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे ताकि बसपा के नेतृत्व में उनके आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता को मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद।

अवैध घुसपैटिए भारत में किसी कानूनी अधिकार के हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध रूप से देश में घुसे प्रवासी और घुसपैटिए भारत के किसी भी कानूनी अधिकार के हकदार नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह टिप्पणी पांच रोहिंया अवैध प्रवासियों की गुप्तशुदांगो से जुड़ी हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान की। ये रोहिंया हिरासत में लिए जाने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने रोहिंयाओं को शरणार्थी कहकर संबोधित किया, जिस पर सीजेआई ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अदालत मानवीय आधार पर ही जा सकती। इनके मामले को देख रही है, लेकिन इससे उनका कानूनी दर्जा -शरणार्थी- नहीं होेगा। कोर्ट ने उम्मीद

जाता। सीजेआई ने तलख लहजे में पूछा, पहले आप अवैध तरीके से सीमा पार करते हैं - सुरंग खोदकर या बाड़ कूटकर भारत में घुसते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, तो मुझे भोजन, आश्रय, बच्चों को शिक्षा प्रदान न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक बार अवैध प्रवासी भारत में दाखिल हो जाते हैं, तो वे तुरंत सुरक्षा अधिकारों पर दावा ठेकने लगते हैं। लेकिन भारत के अपने लाखों गरीब नागरिक हैं, जिनका इन सीमित संसाधनों पर पहला हक है, न कि अवैध घुसपैटियों का। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत में किसी भी अवैध प्रवासी को यातना नहीं दी जा सकती। मानवीयता का तकाजा है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार न हो। कोर्ट ने उम्मीद

जताई कि देश का हर नागरिक, खासकर पूर्वीतर और पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोग, अवैध घुसपैट को गंभीरता को समझते हैं। पीठ ने 2005 के ऐतिहासिक सरवानद सोनोबाल मामले का जिक्र करते हुए दाव दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने तब असम में बांग्लादेशी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण की श्रेणी में रखा था और केंद्र को अनुच्छेद 355 के तहत राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता हैबियस कॉर्पस की आड़ में सरकार से डिपेंडेंशन प्रक्रिया, विदेशी सरकारों से बातचीत और गोपनीय सरकारी फाइलों की जानकारी मांग रहे हैं, जो पूरी तरह जासूसी के तहत हो सकती है। पीठ ने मामले को अगली

सुनवाई 16 दिसंबर निर्धारित करते हुए सभी संबंधित रोहिंया मामलों को एक साथ जोड़ने का फैसला किया। इससे पहले मई 2024 में जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली में रह रहे रोहिंया प्रवासियों के संभावित निर्वासन पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस और प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि म्यांमार लौटने पर रोहिंयाओं का नर्संहार हो सकता है, इसलिए उन्हें भारत में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में कहीं भी रहने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। विदेशी नागरिकों का नियमन विदेशी अधिनियम के तहत हो होगा।



रोहिंया मुद्दा लंबे समय से विवादास्पद रहा है। म्यांमार की सेना इन्हें बांग्लादेशी घुसपैटिया मानती है और नागरिकता देने से इनकार करती है। 2017 के बाद बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से बचकर लाखों रोहिंया पहले

बांग्लादेश और फिर वहां से भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहुंचे। भारत इन्हें शरणार्थी का दर्जा देने से लुप्ततार इनकार करता रहा है।

बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ आज



नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ गुरुवार को, बाल विवाह को समाप्त करने के राष्ट्रीय मिशन के एक साल पूरे होने के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा।। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर इसका शुभारंभ करेंगी। मूल अभियान की शुरुआत 27 नवंबर 2024 को की गई। 100 दिन के अभियान की रणनीति तीन चरणों में होगी। पहला चरण (31 दिसंबर 2025 तक) स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां (डिबेट, निबंध, शपथ ग्रहण)। दूसरा चरण (31 जनवरी 2026 तक) धार्मिक नेताओं, सामुदायिक प्रभावकारों और विवाह सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर बच्चों के अधिकारों का संदेश फैलाना। तीसरा/अंतिम चरण (1 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक) ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव पारित करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शिक्षा मंत्रालय। यह अभियान नागरिकों, संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं से सहयोग की अपील करता है ताकि बाल विवाह को समाप्त करने के भारत के संकल्प को पुरा किया जा सके।

दो दिन बाद मौसम लेगा करवट: पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, कई इलाकों में भारी बारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। आने वाले दो दिनों में मौसम करवट लेने जा रहा है। जिसके चलते दिल्ली-एनसीआर में हाड़ कंपाने वाली ठंड की आहट सुनाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में हाड़ गलाने वाली ठंड के साथ कोहरा भी कहर बरपाएगा। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारा तेजी से नीचे आएगा और शीत लहर का प्रकोप और बढ़ेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 7.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कोहरे की चादर ने दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में ले लिया है। आईएमडी ने 5 दिसंबर को शीत लहर की चेतावनी दी है जिसके साथ न्यूनतम पारा गिरकर 6 डिग्री तक जा सकता है। दिसंबर का पहला दिन 5.7



डिग्री के साथ अभी तक का सबसे सर्द दिन रहा था। मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिसंबर से मौसम फिर बदलेगा और गलाने वाली ठंड का अहसास राजधानी के लोगों को हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मार कम नहीं हुई है। आनंद विहार और चांदनी चौक

जैसे इलाकों में एक्ज्यूआई लगातार 400 के पार बना हुआ है। चूँकि दिल्ली-एनसीआर में अभी बारिश के कोई आसार नहीं हैं इसलिए वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। 6 दिसंबर से कोहरा और घना होने की चेतावनी जारी की गई है। मेटियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के हेडमहेश

राज्यसभा में हलाल सर्टिफिकेशन पर हुई गर्मा-गरम बहस

–मांस के अलावा दूध, चीनी, तेल और सीमेंट पर भी सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गर्मा-गरम बहस हुई। महाराष्ट्र से भाजपा सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा, हलाल केवल मांस से संबंधित एक धार्मिक और आस्था-संकेतित प्रक्रिया है,



लेकिन इसके दायरे को कई अन्य पदार्थों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मांस के अलावा दूध, चीनी, तेल और यहां तक ​​कि सीमेंट, प्लास्टर और अन्य निर्माण सामग्री को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो अताकिंक और आशंकाओं को पैदा करने वाला है।

भाजपा सांसद डॉ. कुलकर्णी ने कहा, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां विभिन्न आस्थाओं के लोग रहते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन केवल मुस्लिम आस्था से जुड़ा विषय है,

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मांस पर हलाल सर्टिफिकेशन केवल सरकारी निकाय द्वारा दिया जाए, न कि किसी धार्मिक संस्था द्वारा। उनका यह भी कहना था कि गैर-मांस खाद्य पदार्थों और गैर-खाद्य वस्तुओं पर हलाल सर्टिफिकेशन देने का कोई आधार नहीं है और इससे धर्मनिरपेक्षता और सविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। सांसद ने कहा कि इस तरह के कदम से उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता बाधित होती है और सामाजिक रूप से मतभेद बढ़ सकते हैं।

सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं द्वारा चार्जस लगाए जाने से बाजार में कीमते बढ़ती हैं और उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से इसका धुगतान करना पड़ता है। उन्होंने इसे

उपभोक्ता स्वतंत्रता और बाजार पारदर्शिता के लिए हानिकारक बताया। डॉ. मेधा ने मेडिकल अध्ययनों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि हलाल प्रक्रिया से मांस में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. कुलकर्णी ने कहा, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां विभिन्न आस्थाओं के लोग रहते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन केवल मुस्लिम आस्था से जुड़ा विषय है,